

युवाओं को उद्यम के लिए 13 हजार करोड़ के लोन देंगे बैंक

जागरण संवाददाता • लखनऊ : राजधानी के उन युवाओं के लिए सुखद खबर है जो अपना करोबार या कोई उद्यम लगाना चाहते हैं। स्वरोजगार के लिए इस वित्तीय वर्ष के बचे चार महीनों में बैंकों की तरफ से 13 हजार करोड़ के लोन जारी होंगे, जिसके लाभार्थियों को चिह्नित करने के लिए उद्योग विभाग और बैंक मिलकर अभियान चलाएंगे। जिले के बैंकों ने 37 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा था जिसमें से 24 हजार करोड़ से अधिक के आवेदनों को हरी झंडी दिखा दी गई है।

प्रत्येक गांव में न्यूनतम दस इकाइयों के लक्ष्य हासिल करने के लिए डीएम सूर्यपाल गंगवार ने उद्योग विभाग को निर्देश दिए हैं। गावों में रोजगार से आर्थिक समृद्धि के साथ युवाओं का पलायन रुकेगा। मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान क्यों हैं खास

24560 करोड़ के लोन को बैंकों ने अभी तक दिखाई हरी झंडी

05 लाख रुपये का लोन बिना किसी गारंटी और ब्याज के मिलेगा

21 से चालीस वर्ष के बीच युवा कर सकते हैं आवेदन

- न्यूनतम योग्यता जूनियर हाईस्कूल, इंटरमीडिएट को प्राथमिकता
- नश्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, कौशल उन्नयन अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शैक्षिक संस्थान से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री आदि।



युवा उद्यमी और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन सहित जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनमें से सभी से आवेदनों का चयन करके लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इनमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सबसे खास है। इसमें पांच लाख रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज और गारंटी के दिया

जाएगा। इसके लिए लखनऊ में साढ़े तीन हजार लोगों को चिह्नित किया जाना है। उद्योग विभाग और बैंक मिलकर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के लिए युवाओं को चिह्नित करेंगे।

सोमवार को हुई जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक मनीष पाठक ने

10 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी सव्सिडी परियोजना लागत का

01 रुपया प्रति ट्रांजेंक्शन डिजिटल ट्रांजेंक्शन के सापेक्ष तथा अधिकतम दो हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान देय

दिए कि प्रत्येक बैंक शाखा में सरकारी योजनाओं में लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारित किया जाए। जिनका आवेदन निरस्त किया जा रहा है उन्हें को बताया जाए कि लोन किस आधार पर पास नहीं किया जा रहा है। अग्रणी जिला प्रबंधक मनीष पाठक ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहले छह महीने में ही जिला वार्षिक ऋण योजना के कुल 37,308 करोड़ के सापेक्ष 24,560 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि ऋण-जमा अनुपात 45.31 प्रतिशत रहा जिसको लेकर जिलाधिकारी चिंता जताई। डीएम ने भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक व आइसीआईसीआई बैंक को निर्देश दिए कि जिनका ऋण जमा अनुपात 60 प्रतिशत से कम है उसे बढ़ाया जाए।

बताया कि वार्षिक ऋण योजना के प्रथम छमाही में ही 66 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन, नाबार्ड डीडीएम कृष्ण कुमार ओझा और भारतीय रिजर्व बैंक से प्रबंधक ऋणभ सक्सेना भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने डीआईसी को निर्देश